एसिआन के साथ भारत का विकास सहयोग

VANI
Celebrating 30 years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

एसिआन के साथ भारत का विकास सहयोग

फरवरी 2019

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रकाशक का आभार प्रकट करते हुए, पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

सहायताः हेनरिच बोल स्टिफटुंग

हिन्दी अनुवादः डॉ. यश चौहान

प्रकाशकः
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सैक्टर, द्वारका,
नई दिल्ली 110 077
फोनः 011–40391661, 40391663
टेलिफैक्सः 011–49148610
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट :www.vaniindia.org

डिजाइन एवम प्रिंट :
प्रिंट वर्ल्ड # 9810185402
ईमेल : printworld96@gmail.com

एसिआन के साथ
भारत का विकास सहयोग

विषय सूची

आमुख.. 03

अध्याय 1: प्रस्तावना.. 05

अध्याय 2: व्यापार और आर्थिक गतिशीलता... 08

अध्याय 3: सामाजिक मुद्देः चुनौतियां और अंतर.. 10

अध्याय 4: एसिआन और भारत में स्थिरतापूर्ण विकास हासिल करना............. 12

अध्याय 5: नागरिक समाज की सलंग्नता... 14

निष्कर्ष 18

आमुख

एसिआन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो आर्थिक और सामाजिक विकास, संपर्क और सहयोग के अनेक अवसर प्रदान करता है अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपर्क के कारण भारत एसिआन का एक स्वााभाविक साझेदार है। इन देशों के आपसी हित पिछले 25 वर्षों की साझेदारी से चालित रहे हैं; और व्यापार, संपर्क, संस्कृति और सुरक्षा आदि सहित अनेक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर भारत और एसिआन के द्वारा सहयोग को बढ़ाने के साथ–साथ यह संबंध गहन होगा। भारत और एसिआन द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) के माध्यम से एक व्यापक फ्री ट्रेड एरिया की दिशा में कार्य हमारे साझे क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को प्रोन्नत करने की कुंजी होगा।

भारत और एसिआन के बीच आर्थिक संलग्नता ठोस गति से बढ़ रही है, पर फिर भी ऐसी चुनौतियां मौजूद हैं जिनके लिए प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप ही जरूरत होगी। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन और ग्रामीण/शहरी तथा जेंडर विभाजन के वातावरण में भारत और एसिआन को समान अवसर, परिणाम और सामाजिक सचलता सुनिश्चित करनी चाहिए और समावेशपूर्ण विकास को प्रोन्नत करने में और अधिक ज्ञान–साझेदारी और सर्वोत्तम तौर–तरीकों को सुगम बनाना चाहिए। इसमें संपर्क तथा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, निजी क्षेत्र और सरकार के बीच परामर्श को शामिल किया जाना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन मौसम बदलाव के क्षेत्र में संबंधित हितधारकों और सरकार के बीच संवाद; साथ ही शोध, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन के रूप में एसिआन को खतरों से बचना चाहिए और एसिआन देशों के लोगों, सदस्य देशों और साझेदारों की जरूरतों और मांगों को लेकर लचीलापन अपनाना चाहिए। यहीं पर नागरिक समाज संगठनों की मजबूत सामाजिक उपस्थिति आवश्यक हो जाती है, जब सहभागिता सुनिश्चित करने और विकास चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए एसिआन का अगला मार्ग मानचित्र तैयार किया जा रहा है।

एक भू राजनीतिक असुरक्षा के चरण में भारत और एसिआन को जबर्दस्त सहयोग–अवसरों का लाभ उठाने में एक अनिवार्य भूमिका निभानी है। वर्तमान और बदलते वातावरण के साथ उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने में भारत और एसिआन

उपयुक्त साझेदार सिद्ध हुए हैं। इसलिए भारत–एसिआन में भविष्य में बदलाव की संभावना निहित है और सहयोग का नया चरण नये तरीकों का मानचित्रण करने और इस जबर्दस्त साझेदारी की क्षमता को सिद्ध करने का एक अवसर है। यह अध्ययन शोध नागरिक समाज के परिप्रेक्ष्य से भारत – एसिआन साझेदारी की छानबीन करता है।

मैं इस अध्ययन का प्रारूपित करने और इसके लेखन के लिए वाणी की टीम और वाणी की कार्यक्रम अधिकारी श्रुति शर्मा को तथा मार्गदर्शन के लिए वाणी कार्यक्रम प्रबंधक, श्री अर्जुन फिलिप्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं इस अध्ययन को सहायता प्रदान करने के लिए हेनरिच बोल स्टिफटुंग का आभार भी व्यक्त करता हूं।

साभिवादन

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अध्याय 1: प्रस्तावना

एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ऐशियन नेशंस (एसिआन) की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकाक में हुई थी और इसमें पांच देशों – इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और थाईलैंड – ने एसिआन घोषणा (बैंकाक घोषणा) हस्ताक्षरित की थी। ये देश एसिआन के संस्थापक सदस्य हैं बाद में ब्रनेई, दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यानमार और कंबोडिया इसमें शामिल हुए और सदस्यों की संख्या दस हो गई। इस एसोसिएशन का गठन सदस्य देशों के बीच और अन्य एशियाई देशों के साथ अंतः सरकारी सहयोग एवम सुविधाओं, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक – सांस्कृतिक सहयोग को प्रोतसाहित करने के लिए किया गया था। एसिआन 60 करोड़ लोगों का जो विश्व के सर्वाधिक गतिशील देशों के दस देशों में रहते हैं, उनका एक समुदाय है।

एसिआन क्षेत्र विश्व के सबसे तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से है। पिछले 50 वर्षों में एसिआन की सामाजिक और आर्थिक प्रगति असाधारण रही है। एसिआन ने एसिआन क्षेत्र के भीतर सहयोग को तेज किया और इस क्षेत्र के विकास संबंधी अंतरों को दूर किया। 22 नवम्बर 2015 में कुआला लमपुर में एक घोषणा को हस्ताक्षिरित करके एसिआन को एक समुदाय घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत समुदाय के रूप में और अधिक सुदृढ़ीकरण, एकीकरण और मजबूत समरसत्ता का उल्लेख किया गया है। आरंभ से ही एसिआन और भारत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। उनके साझी गहन संस्कृति और ऐतिहासिक संपर्क रहे हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक संबंध मजबूत रहे हैं; पर उन्होंने आर्थिक नीति के मामले में अलग–अलग रास्ते अपनाये हैं। एसिआन क्षेत्र को आरंभिक उदारीकरण से लाभ प्राप्त हुए, पर भारत इस प्रमुख घटनाक्रम की दृष्टि से पीछे रहा। 1990 में डॉ. मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसने भारत के लिए नये अवसरों के दरवाजे खोले। भारत–एसिआन संबंध "लुक ईस्ट" नीति के मुख्य आधार के रूप में उभरे हैं। इस नीति को 1990 के दशक के आरंभ में सूत्रित किया गया था जिसने 1992 में भारत को एसिआन के क्षेत्रीय साझेदार से 2012 में एक रणनीतिक साझेदार बनाया।

भारत दक्षिण पूर्व एशिया को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जहां वह अपने दर्जे को ऊपर उठा सकता है; और वह अपने भविष्य को दक्षिण–पूर्व एशिया के भाग्य से जोड़ कर देखता है। एसिआन–भारत संबंधों और क्षेत्रीय एकीकरण को बल प्रदान करने के लिए भारत की "लुक ईस्ट" नीति को 2014 में बदलकर एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संपर्कों को बल

पहुंचाना और एशिया–प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना था।

भूराजनीतिक अनिश्चितता एसिआन भारत सहयोग को नया प्रोत्साहन प्रदान करती है क्योंकि दोनों पक्षों के हित इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा की दृष्टि से समान हैं। भारत रणनीतिक दृष्टि से हिन्द महासागर से प्रशांत महासागर तक के प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है। ये मार्ग अनेक एसिआन सदस्य राज्यों के व्यापार मार्ग हैं और इसलिए व्यापार के इस महत्वपूर्ण समुद्री माध्यम के संरक्षित करने में दोनों पक्षों का साझा हित है। इसके अलावा भारत और एसिआन को उच्च गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) को संपन्न करने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे एक एकीकृत एशियाई बाजार का निर्माण होगा जो विश्व की आधी आबादी और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक तिहाई को शामिल करेगा।

नियम–कायदों को व्यवस्थित बनाने से दोनों दिशाओं में निवेश बढ़ेंगे, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के पूरित किया जा सकेगा और इस क्षेत्र में "भारत–निर्मित" निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। भारत एसिआन के परामर्शदाता दायरे के अंतर्गत अपने सोचे समझे कदमों के प्रभाव से सम्मलित हुआ है।

वर्ष 2017 में भारत और एसिआन ने शिखर–सम्मेलन स्तर की साझेदारी के 15वें वर्ष और साथ ही संवाद साझेदारी के 25वें वर्ष को चिन्हित किया। दिल्ली घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है जिसका उद्देश्य नागरिक समाज को आर्थिक विकास और सामाजिक क्षेत्र में संलग्न करने हेतु एकजुट करना और साथ ही संसाधन–जनन एवं भारत के विकास सहयोग के मुद्दों में नेताओं को शामिल करना है। दिल्ली संवाद भूमंडलीय भूराजनीतिक आंदोलनों और एसिआन–भारत संबंधों पर उनेक प्रभाव का जायजा लेने और इस उल्लेखनीय संबंध को भविष्य की दिशा के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया है। व्यापक आर्थिक सहयोग पर एसिआन, भारत ढांचा समझौता भारत और एसिआन के बीच इंडोनेशिया के बाली में 8 अक्टूबर 2003 को हस्ताक्षरित हुआ था जिसका उद्देश्य भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचे को संस्थागत रूप देना था।

भारत अनेक प्रकार के प्रयास करता रहा है और एफ.आई.डी.सी. को आरंभ किये जाने के साथ ही सरकार और नागरिक समाज संगठनों के बीच संलग्नता को बल प्राप्त हुआ। इसके पीछे विचार यह था कि विकास सहयोग के विभिन्न पहलुओं की छानबीन की जाये। यह एक बहु–हितधारक मंच के रूप में उभरा है जिसमें सरकार, नागरिक समाज संगठनों, अकादमिक जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत और एसिआन के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं क्योंकि दोनों पक्ष भविष्य की प्रगति के

लिए तैयार हैं। इस प्रकार के मंच के माध्यम से भारत अपने नेटवर्कों या संपर्क तंत्रों को मजबूत बना सकता है। रणनीतिक प्रबंधों में इस साझेदारी के संबंध में संभावना और उत्तरदायित्व की भावना निहित है। भारत और एसिआन सदस्य देशों का इतिहास और संस्कृति के पास विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में अधिक संरचित और दीर्घकालिक आदान–प्रदान की शक्ति और क्षमता है।

एसिआन और अन्य साझेदारियां

एसिआन भूमंडलीय स्तर पर संपर्कों के साथ–साथ क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय स्तर के देश भी एसिआन की प्रतिबद्धता में भाग ले रहे हैं और योगदान कर रहे हैं। 1970 के दशक के आरंभ में राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के साथ सहयोग के माध्यम से राष्ट्र संघ और एसिआन के बीच संबंधों की शुरूआत हुई। एसिआन को उसके आर्थिक सहयोग कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने और एसिआन को उसके क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण प्रयास में बेहतर सहायता करने के लिए 1977 में यू.एन.डी.पी. द्वारा एक दो वर्षीय अध्ययन प्रायोजित किया गया।

क्षेत्रीय स्तर पर एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) एसिआन के साथ घनिष्ट रूप से मिलकर काम करता है और एसिआन क्षेत्र में एकीकरण तथा स्थिरतापूर्ण विकास की तलाश में साझे लक्ष्यों और लक्ष्य से प्रतिबद्ध है। एशियाई विकास बैंक उप क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग कार्यक्रमों के माध्यम से एसिआन को सीधे–सीधे सहायता प्रदान करता है और उसने एसिआन की विकास कार्यावली को प्रोन्नत करने में सहायता प्रदान की है। इस रणनीतिक सहायता के अंतर्गत अनेक रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैंः अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का विकास, व्यापार और परिवहन सुविधा, आदि।

इसके साथ ही एसिआन सार्क और दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है। सार्क और एसिआन के बीच स्वस्थ व्यापारिक संबंध और समझौता है जैसे कि ए.आई.एफ.टी.ए. और ए.पी.एफ.टी.ए. जो सदस्य देशों के बीच व्यापार के विस्तार के मार्ग के रूप में कार्य करते है। किन्तु एसिआन और सार्क और बीच क्षेत्रीय सत्ता संतुलन कमजोर है क्योंकि केवल भारत और बंगलादेश को ही क्षेत्रीय मंच साझेदारों का दर्जा दिया गया है। सार्क विभिन्न मुद्दों के समाधान और अपने आर्थिक उत्थान के लिए एसिआन के साथ घनिष्ट रूप से मिल कर काम कर सकते हैं और इसी के साथ आर्थिक स्वतंत्रता तथा एसोसिएशन के लिए अधिक अवसर प्रदान कर सकता है।

अध्याय 2ः व्यापार और आर्थिक गतिशीलता

अपनी स्थापना के समय से ही एसिआन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत रही है और उसका जी.डी.पी. 2.55 ट्रिलियन अमरीकी डालर है। वर्ष 2016 में एसिआन की सकल जी.डी.पी. आकार की दृष्टि से विश्व में छठवें स्थान पर और एशिया में तीसरे स्थान पर थी। एसिआन का कुल व्यापार पिछले दशक में बढ़ा है और 2007 में 1.6 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 2016 में 2.3 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया है जो कि विश्व व्यापार का 7.1 प्रतिशत हिस्सा है; और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है। अतः – एसिआन बाजार सामूहिक रूप से बढ़ता रहा है; उसमें 21 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि अतः– एसिआन आयातों में 1995 में 16.5 प्रतिशत से 2016 में 22.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही एसिआन क्षेत्र को बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह (इनफ्लो) से लाभ प्राप्त हुआ है।

भारत की विविधातापूर्ण अर्थव्यवस्था ने भारत को अनुमानित जी.डी.पी. के आधार पर विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और वह 2016 में पी.पी.पी. की दृष्टि से मापित जी.डी.पी. के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है; उसकी संवृद्ध दर (ग्रोथ रेट) वित्त वर्ष 2016–17 में 7.1 प्रतिशत थी। इसके अलावा भारत की व्यापार अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में 4.8 प्रतिशत सी.ए.जी.आर. की दर से स्थिरतापूर्वक बढ़ती रही है; और वह वित्त वर्ष 2016 में 660.6 बिलियन अमरीकी डालर थी। इसके बाद भूमंडलीय व्यापार (उत्पाद और सामान) में भारत के हिस्से में वृद्धि हुई तथा वह सेवाओं के शुद्ध निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को बनाये रखने में सफल रहा है। इसके फलस्वरूप भारत 2016 में विश्व में आठवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक थे। वित्त वर्ष 2016–17 में भारत में एफ.डी.आई. आप्रवाह (इनफ्लो) 60.1 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र, आदि शामिल था। भारत से एफ.डी.आई. आउटफ्लो में वित्त वर्ष 2015–16 में 22 बिलियन अमरीकी डालर था जो मुख्यतः वित्तीय, बीमा और व्यवसाय सेवा क्षेत्र की ओर निर्दिष्ट था, इसके बाद कृषि और खनन तथा विनिर्माण, आदि शामिल हैं।

एसिआन–भारत व्यापार और आर्थिक संबंध

जहां एसिआन–भारत फ्री ट्रेड एरिया जुलाई 2015 से पूरी तरह से क्रियाशील था,

वहीं भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) वार्ताओं में सक्रियता से संलग्न था। इन वार्ताओं में एसिआन और उसके छह फ्री ट्रेड एरिया साझेदार शामिल रहे। इस साझेदारी के संपन्न होने पर यह सबसे बड़ी क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था होगी। गत वर्षों में भारत और एसिआन विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे हैं।

एसिआन के साथ भारत को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश	एसिआन में भारत के लिए निवेश के अवसर
• भारत और एसिआन की आर्थिक संलंग्ता में वृद्धि हुई • एसिआन के साथ भारत के कुल व्यापार में ढिलाई आई (यह 2012 में 75 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2016 में 64.6 बिलियन हो गया) • समय के साथ निर्यातों और आयातों में गिरावट। निर्यात 2016 में 32.3 बिलियन अमरीकी डालर घटकर 26.4 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गये; आयात 2016 में 42.7 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 38.2 बिलियन अमरीकी डालर पर आये)	• अपने 10 विविध बाजारों के साथ एसिआन देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं जबकि कुछ विकासशील अवस्था में हैं; व्यापार और निवेश में व्यापक अवसर मौजूद हैं। • ए.आई.जी. और ए.आई.ए. – जो एसिआन व्यापक निवेश समझौते का परिणाम हैं– के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत – एसिआन के निवेश में सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।
भारत–एसिआन व्यापार और आर्थिक सहयोग	**एसिआन–भारत कार्य–योजना**
• एसिआन–भारत फ्री ट्रेड एरिया इन समझौतों के हस्ताक्षरित होने के साथ पूर्ण हुआ हैः वर्ष 2009 में सामानों में एसिआन–भारत व्यापार और 2015 में सेवाओं में एसिआन–भारत व्यापार • अप्रैल 2007 से मार्च 2015 के दौरान भारत से एसिआन को संचित एफ.डी. आई. आउटफ्लो 38.67 बिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल 2000 से और दिसंबर 2016 के बीच एसिआन से भारत में एफ.डी.आई. इनफ्लो 54.97 बिलियन अमरीकी डालर था।	• शांति, प्रगति और साझी समृद्धि के लिए एसिआन–भारत साझेदारी का कार्यान्वयन करने के लिए एक कार्य–योजना (2004–2010) तैयार की गई। वर्ष 2016–2020 के लिए तीसरी कार्य–योजना तैयार की गई। • वर्ष 2016–2020 के लिए तीसरी कार्य–योजना को अंतिम रूप दिया गया है और 2016–18 के लिए प्राथमिक कार्यकलापों की सूचियों को नियोजित किया गया है। इसमें विशेषकर उनके आईएआई कार्यक्रम के अंतर्गत एसिआन सदस्यों के बीच के विकास अंतरों को कम करने के लिए क्षमता–निर्माण और विकास के लक्ष्य के साथ क्रियाशील सहयोग का परिकल्पित किया गया है।

अध्याय 3: सामाजिक मुद्देंः चुनौतियां और अंतर

विश्व के अनेक देश सामाजिक मुद्दों और विकास संबंधी अंतरों की स्थिति से निबट रहे हैं। ये तब घटित होते हैं जब देश के बीच आय या अन्य सामाजिक घटनाक्रम में अंतर होते हैं। एसिआन की एकीकरण प्रक्रिया के बावजूद, उसके सदस्य देश और साझेदार अभी भी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मुद्दों और चुनौतियां का जैसे मौसम परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का सामना कर रहे हैं। क्योंकि एसिआन विषमरूपी देशों का समूह है और उनके बीच व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास असमानताएं मौजूद हैं, इसलिए उनके विकास के स्तरों और राजनीतिक प्रणालियों आदि में अंतर है। एसिआन सचिवालय ने हाल ही में जकार्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका उदेद्श्य सामाजिक मुद्दों के मूल कारणों से निबटने हेतु रणनीतिक निर्देश तैयार करना था। इस सम्मेलन में साझेदारों, ए.एस.सी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों आदि ने भाग लिया। सम्मेलन का लक्ष्य एक शांतिपूर्ण, समावेशपूर्ण, स्वस्थ, लचीले और समरसत्तापूर्ण समाज के लिए रोकथाम की संस्कृति पर एसिआन घोषणा (सी.ओ.पी.) को प्रोन्नत करना था। इस घोषणा को फिलिपीन्स के मनीला में 31वें एसिआन सम्मेलन में नवम्बर 2017 को स्वीकृत किया गया था।

एसिआन के महासचिव, लिम जोक होई ने रोगों के फैलाव, नशीले पदार्थों की समस्या, मौसम परिवर्तन, अपराध, शिक्षा आदि के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों को अपने अभिभाषण में उठाया था। एसिआन देशों को मौसम बदलाव की वजह से हर वर्ष 4.4 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान उठाना पड़ता है। महासचिव ने समस्या के मूल कारण से निबटने के लिए सीधे–सीधे हस्तक्षेप के बजाये रोकथामकारी तरीके पर बल दिया। उन्होंने रोकथाम के विचार के इन छह पहलुओं को सामने रखा थाः सुशासन, सक्षम करना, पर्यावरण की देखरेख, जागरूकता, सम्मान, स्वस्थ जीवन शैली और संयमन के मूल्य। अपने साझेदारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सहयोग की भूमिका को स्वीकार करते हुए, एसिआन रोकथाम की संस्कृति (सी.ओ. पी.) को बढ़ावा देने के लिए प्रभावकारी समाधानों और कार्य की सर्वोत्तम रीतियों की तलाश करता है।

एसिआन में, और विशेषकर कम विकसित सदस्यों देशों और समृद्ध तथा उच्च रूप से विकसित देशों के बीच विकास संबंधी अंतरों और असमानताओं के संबंध में देश और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करने और नीति निर्माताओं को दिशा–निर्देश प्रदान करने की जरूरत है। ओ.ई.सी.डी. विकास केन्द्र और एसिआन सचिवालय द्वारा तैयार किये गये विकास अंतर कमी संकेतक (एन.डी.जी.आई.) का प्रगति का मापन करने

और देशों के बीच विकास संबंधी अंतरों को दूर करने के लिए उपयोग किया गया। एन.डी.जी.आई. में ये छह क्षेत्र शामिल किये गये हैं: मानव संसाधन विकास, व्यापार और निदेश, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और निर्धनता।

जहां तक भारत के सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों का संबंध है, उस विकास मार्ग उसकी अनूठी संसाधन निधि, आर्थिक और सामाजिक विकास की सर्वाधिक प्रमुख प्राथमिकताओं, निर्धनता उन्मूलन और लम्बे समय से देश के सम्मुख उपस्थित अनेक अन्य मुद्दों पर आधारित हैं। किन्तु भारत का लक्ष्य न केवल स्थानीय, पर साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इन सामाजिक मुद्दों के प्रति एक प्रभावकारी, सहयोगपूर्ण और समतापूर्ण दृष्टिकोण स्थापित करना है; किन्तु यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक उत्तरदायी और प्रबुद्ध सदस्य के रूप में – जो विश्व को प्रभावित करने वाली भूमंडलीय चुनौती के समाधानों में योगदान कर सके–भारत की भूमिका के अनुरूप होना चाहिए। जहां भारत सरकार देश की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में निर्धनता में कमी लाने और आर्थिक विकास पर बल देती है, वहीं घरेलू उत्सर्जन (एमिशन) में कमी के हाल के उदाहरण यह संकेत देते हैं कि भारत पर्याप्त कदम उठा रहा है और उसने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूप से मौसम परिवर्तन में और अधिक सक्रिय संलग्नता के संकेत प्रस्तुत किये हैं। भारत मौसम परिवर्तन पर राष्ट्र संघ ढांचा सम्मेलन की बहुपक्षीय वार्ताओं में सकारात्मक, रचनात्मक और अग्रदृष्टिपूर्ण तरीके से सक्रियता से संलग्न रहा है। हमारा भूमंडलीय दृष्टिकोण मौसम परिवर्तन पर राष्ट्र संघ ढांचा सम्मेलन में उल्लिखित समान और विभेदित उत्तरदायित्वों और अपनी–अपनी क्षमताओं के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को साथ–साथ आगे बढ़ाने वाला स्थिरतापूर्ण विकास का मार्ग तैयार करने के लिए मौसम परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य–योजना मौजूद है।

अध्याय 4: एसिआन और भारत में सस्टेनेएबल डवलेपमेंट गोल्स हासिल करना

सस्टेनेएबल डवलेपमेंट गोल्स अपनाने के पीछे मूल विचार यह था कि “किसी को पीछे नहीं छोड़ो” के सिद्धांत के साथ निर्णयकता, व्यापकता, सार्वभौमिकता और समावेश लाया जाये। सस्टेनेएबल डवलेपमेंट गोल्स (एस.डी.जीज) नये सार्विक लक्ष्य हैं जिन्हें भारत सहित 193 देशों ने अपनाया है। इनमें 17 लक्ष्य और 169 ध्येय शामिल हैं जो एम.डी.जीज. की सफलताओं के आधार पर बने हैं और इनमें मौसम परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, स्थिरतापूर्ण उपभोग, शांति और न्याय जैसे नये क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एस.डी.जीज. आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों को एकीकृत करते हैं। ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं और तरह से इनमें एक की सफलता में दूसरे लक्ष्य से जुड़े मुद्दों से निबटने का कार्य शामिल होगा। इन लक्ष्यों और उद्देश्य की समय–सीमा 2030 है।

सस्टेनेएबल डवलेपमेंट की दिशा में एसिआन का दृष्टिकोण

एसिआन दो पराचर–जुड़ी समानांतर प्रक्रियाओं से प्रतिबद्ध हैं। ये प्रक्रियाएं हैंः एसिआन सामुदायिक विजन 2025 और सस्टेनेएबल डवलेपमेंट के लिए राष्ट्र संघ 2030 एजेंडा। विकास और स्थिरता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्रयास ठोस पर्यावरणगत कदमों और पहलकदमियों को आधार बनाते हैं। एसिआन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उनके स्थिरतापूर्ण, उपयोग, पर्यावरण की दृष्टि से स्थिरतापूर्ण शहरों, समुद्र तटीय और समुद्री वातावरण तथा स्थिरतापूर्ण उपभोग एवं उत्पादन आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है। मौसम परिवर्तन से निबटना भी एक चुनौती है और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत भी है कि मौसम परिवर्तन के संबंध में एसिआन क्षेत्र किस तरह से अपने सहयोग को मजबूत बना सकता है। एसिआन विपदा आपात्कालीन लाजिस्टिक प्रणाली (डी.ई.एल.एस.ए.) और उसके सेटेलाइट वेयरहाउस के माध्यम से विपदा प्रबंधन और विपदा जोखिम कमी के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाना जारी रखे हुए है।

इसके अलावा, वर्ष 2018 के लिए एसिआन सामाजिक–सांस्कृतिक समुदाय (ए.एस.सी.सी.) पिलर की प्राथमिकताएं और जारी कार्य के अंतर्गत रोजगारों को बढ़ावा देना, विकलांग लोगों के अधिकार को मुख्य धारा में लाना और साइबर कल्याण आदि शामिल हैं। ये प्राथमिकताएं 33वें एसिआन शिखर सम्मेलन के समय परिणाम दस्तावेजों के रूप में सामने आयेंगी। ए.एस.सी.सी. पिलर के अंतर्गत 20 युवा

कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की गई जिनमें नेतृत्व, स्वैच्छिक कार्य, रोजगार, लचीलापन, अंतः सांस्कृतिक समझ और जीवन कौशल जैसे विषय शामिल थे। ए.एस.सी.सी. पिलर बाजार की मांगों को पूरा करने हेतु प्रतियोगिता और एसिआन श्रमशक्ति की उत्पादकता में सुधार लाकर श्रम बाजार में लोगों को और अधिक प्रतियोगितापूर्ण बनने के लिए तैयार करने का कार्य करता है।

एसिआन सस्टेनेएबल डवलेपमेंट गोल्स (एस.डी.जीज.) के हासिल करने हेतु प्रतिबद्ध है। ए.एस.सी.सी. पिलर ने एसिआन विजन 2025 और एस.डी.जीज. के बीच पूरकताओं को बढ़ावा देने में एसिआन के सदस्य देशों और साथ एक देश समन्वयक के रूप में थाईलैंड को सहायता प्रदान की है। एसिआन के सामाजिक–सांस्कृतिक सामुदायिक ब्लूप्रिंट में संतुलित सामाजिक विकास और ऐसा स्थिरतापूर्ण विकास – जो हर समय लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके – के बीच संतुलन को प्रोन्नत और सुनिश्चित करने की जरूरत को उजागर किया गया है। इसी के अनुरूप 2030 एजेंडा ऐसा सही ढांचा प्रदान करता है जिसके साथ एसिआन अपने स्थिरतापूर्ण या स्थायित्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ अपने समुदाय निर्माण दृष्टिकोण को शामिल कर सकता है। ये लक्ष्य चार प्राथमिकताओं में प्रतिबिंबित होते हैं; उदाहरण के लिए उद्देश्य 15, उद्देश्य 11, उद्देश्य 13 और उद्देश्य 12। एसिआन और भारत, दोनों ने तीन आयामों – यानी पर्यावरणगत, सामाजिक और आर्थिक आयामों – पर एक समेकित प्रकार से ध्यान देने के लिए एक स्थिरतापूर्ण या स्थायित्वपूर्ण विकास की जरूरत पर बल दिया है।

बढ़ा हुआ संपर्क सीधे–सीधे राष्ट्र संघ 2030 विकास एजेंडा में और एस.डी.जीज. में योगदान कर सकता है। इनसे देश राष्ट्र–पारीय मूल्य श्रृंखलाओं, विस्तारित प्रतियोगिता और उत्पादता से बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं और रोजगार का सृजन कर सकते हैं और निर्धनता में कमी ला सकते हैं। दस सदस्य देशो में स्थायित्वपूर्ण विकास लक्ष्यों (एस.डी.जीज.) का कार्यान्वयन करने वाले प्रभारी सरकारी अधिकारियों; सदस्य संस्थाएं, विकास साझेदार, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्र की स्थानीय स्तर पर विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने मे महत्वपूर्ण भूमिका है– विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से विविध प्रकार के देशों में।

एसिआन विजन का उद्देश्य एक ऐसे एक नियम–आधारित, जन–उन्मुख और जन केंद्रित एसिआन समुदाय का निर्माण करना है जहां उनके लोग उच्च जीवन गुणवत्ता और समुदाय–निर्माण के लाभों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, एसिआन विजन 2025 और एस.डी.जीज. के बीच जो पूरकताएं (कांप्लीमेंटरीज) हैं वे स्थायित्वपूर्ण विकास एजेंडा को हासिल करने में एसिआन की क्षमताओं को सामने लायेंगी और साथ एसिआन क्षेत्र के एकीकरण और विकास में योगदान करेंगी।

अध्याय 5: नागरिक समाज की संलग्नता

नीतिगत निर्णयों का हिस्सा न हो पाने और साथ समाज के लिए अपने कार्य और योगदान के लिए मान्यता न मिलने को लेकर नागरिक समाज लम्बे समय से संघर्ष करता रहा है। भारत में ही नहीं एसिआन के सदस्य देशों में भी नागरिक समाज की यही स्थिति रही है। इस मुद्दे को नवम्बर 2017 में फिलिपींस में आयोजित एसिआन जन मंच (ए.पी.एफ.) के दौरान उजागर किया गया था। इसके अलावा नागरिक समाज के संगठनों ने एसिआन के भीतर अपनी स्थिति और प्रक्रियाओं को विकसित करने में समय लगाया है। जब एसिआन का अगला मार्ग मानचित्र तैयार किया जायेगा तब आम लोगों की आवाज को मुखर करने के लिए सामाजिक उपस्थिति की जरूरत होगी। नागरिक समाज के संगठन विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और वे सरकार और आम लोगों के बीच संपर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए.पी.एफ. रिव्यू के अनुसार एसिआन की प्रतिबद्धता के संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जन भागीदारी को सुगम बनाने हेतु सक्षमकारी वातावरण मौजूद नहीं है। इस प्रकार राज्य के एजेंडा से परे जाकर क्षेत्रीय एकीकरण को हासिल करने, नये विचार विकसित करने तथा सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करने की जरूरत है।

ए.पी.एफ. ने एक क्षेत्रीय समूह के रूप में एसिआन को अधिक समावेशपूर्ण बनाने के लिए नई रणनीतियां तैयार की हैं। निर्णय प्रक्रिया में जन भागीदारी के स्थान को विस्तारित करने के लिए एक जन केंद्रित कार्यावली अपनाने की जरूरत है। चुनौतियों के बावजूद नागरिक समाज के संगठनों और अन्य संस्थाओं को अपने भविष्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय पद्धति की जरूरत है जैसे कि कार्यगत और सेक्टोरल स्तर पर नागरिक समाज संगठनों की संलग्नता। एसिआन के निकायों और संबंधित नागरिक समाज संगठनों ने विपदा राहत से लेकर शिक्षा, मानव अधिकार और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों तक में महत्वपूर्ण कार्य–संलग्नता के उद्देश्य के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु कदम उठाये हैं। यह दृष्टिकोण आकर्षक न दिखता हो, पर जमीनी स्तर पर यह अधिक लाभप्रद रहा है और इसके अलावा इसमें दोनों पक्षों के बीच विश्व और सहजता का स्तर बढ़ा है।

एसिआन के सामने चुनौती यह है कि किस तरह जन केंद्रित क्षेत्रीय संगठन की दिशा में उत्पादक साझेदारी निर्मित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और सदस्य देशों की मानसिकता में बदलाव लाया जाये। इसके अलावा सरकारों और नागरिक समाज

के संगठनों के बीच मतभेद रहे हैं और इसलिए दोनों को एक दूसरे की भूमिकाओं को समझने और उनका सम्मान करने की जरूरत है। दूसरी समस्या है – देशों के बीच महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने हेतु समय पर कार्य उन्मुख प्रत्युत्तर तैयार करना; जैसे कि चीन को प्रभावित किये बिना किस प्रकार अमरीका के सरोकारों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाये। इतना ही नहीं, एसिआन का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय गतिशीलता पर निर्भर करता है; अगर महाशक्तियों के बीच संबंध बिगड़ते हैं तो एसिआन बहुत ही असहज स्थिति में आ जायेगा और उसके सदस्य देशों को एक या दूसरे पक्ष को चुनना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एसिआन के बीच अतः राज्य विवाद गायब नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद जिससे सुरक्षा समुदाय होने के एसिआन के दावे को चुनौती मिली है।

एसिआन को सहयोग द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने के लिए ऐसी चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिएः वर्तमान प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए अवसर। नागरिक समाज के संगठनों को ए.पी.एफ. और ए.एस.सी.एस. जैसी वर्तमान प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसिआन के मुद्दों पर संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है। एक दूसरा उदाहरण है एसिआन सचिवालय को सुदृढ़ बनाना। नागरिक समाज के संगठन समुदाय निर्माण के भाग लेने के लिए उत्साहित और तैयार हैं, पर ऐसे संस्थागत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ए.एस.सी. के संचार संबंधी निर्देश के बिना नागरिक समाज के संगठनों और एसिआन सचिवालय के बीच संचार में सुधार आया है। नागरिक समाज के संगठनों को बाधित करने वाले अन्य मुद्दे हैंः क्षेत्रीय रूप से समस्याओं के आपस में समाधान के लिए तालमेल करना या संस्थागत क्षमताओं का सीमित होना। इस तरह दूसरे कार्य–पक्षों के साथ साझेदारी के अवसर, बाहरी संबंधों और साथ ही अनुभवों के आदान–प्रदान के माध्यम से और ऐसे सहयोग द्वारा प्रस्तुत मंच से प्राप्त सीखों के जरिये नागरिक समाज संगठनों के समन्वय और कार्य–क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।

संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों और एसिआन के बीच निम्न भागीदारी रही है। सीएसओ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ रही है, पर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चुनौतियां उनके सामने अभी भी मौजूद हैं। विकास के लिए नागरिक समाज संगठनों की उपस्थिति नीतिगत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। इस तरह एसिआन के सदस्यों देशों के नागरिक समाज संगठनों की स्थिति का विश्लेषण करना न केवल विश्व स्तर, एसिआन के स्तर पर भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एसिआन क्षेत्र के देशों के नागरिक समाज संगठन तो विकसित हो रहे हैं पर अलग–अलग भूगोल, सामाजिक–राजनीतिक स्थिति और अर्थव्यवस्था के कारण ये सदस्य देश दिशा और स्थिति में हैं।

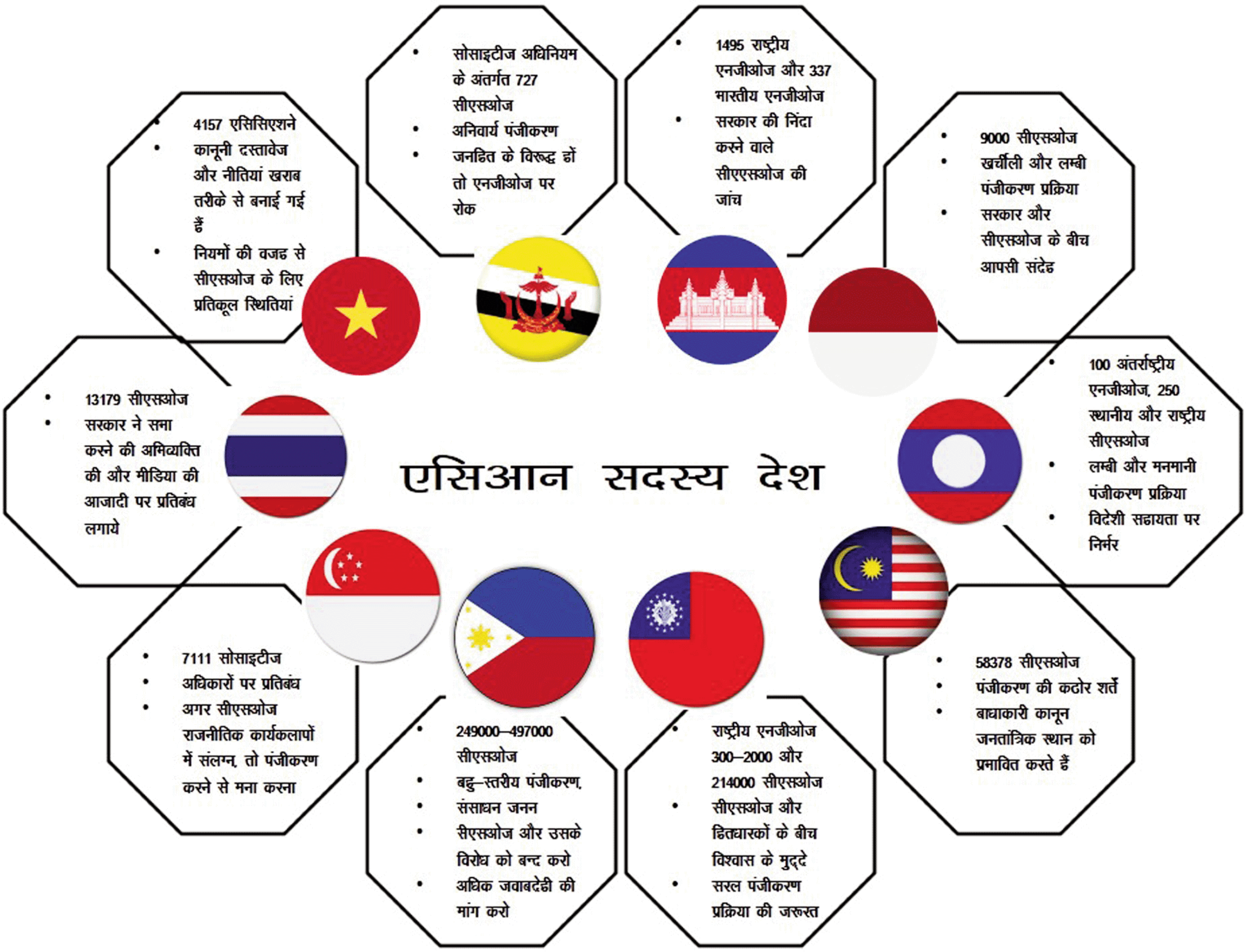

एसिआन न केवल सरकारों के लिए, बल्कि नागरिक समाज के लिए भी अपने विचारों को साझा करने का एक मंच है। एसिआन अपनी पहुंच को बढ़ा सकता है और एसिआन में नागरिक समाज को संलग्न तथा सक्रिय करके, न केवल राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी अधिकतर विषयों को अपनी परिधि में ले सकता है। इससे नागरिक समाज के पुराने पड़ चुके तौर–तरीके में बदलाव ला सकता है और साथ ही एसिआन समुदाय–निर्माण प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो सकते हैं।

एसिआन–भारत सी.एस.ओ. संवाद

नागरिक समाज संगठनों (सी.एस.ओज.) के साथ भारत की संलग्नता बहुपक्षीय स्तर पर विकास सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है और स्थायित्वपूर्ण बदलाव,

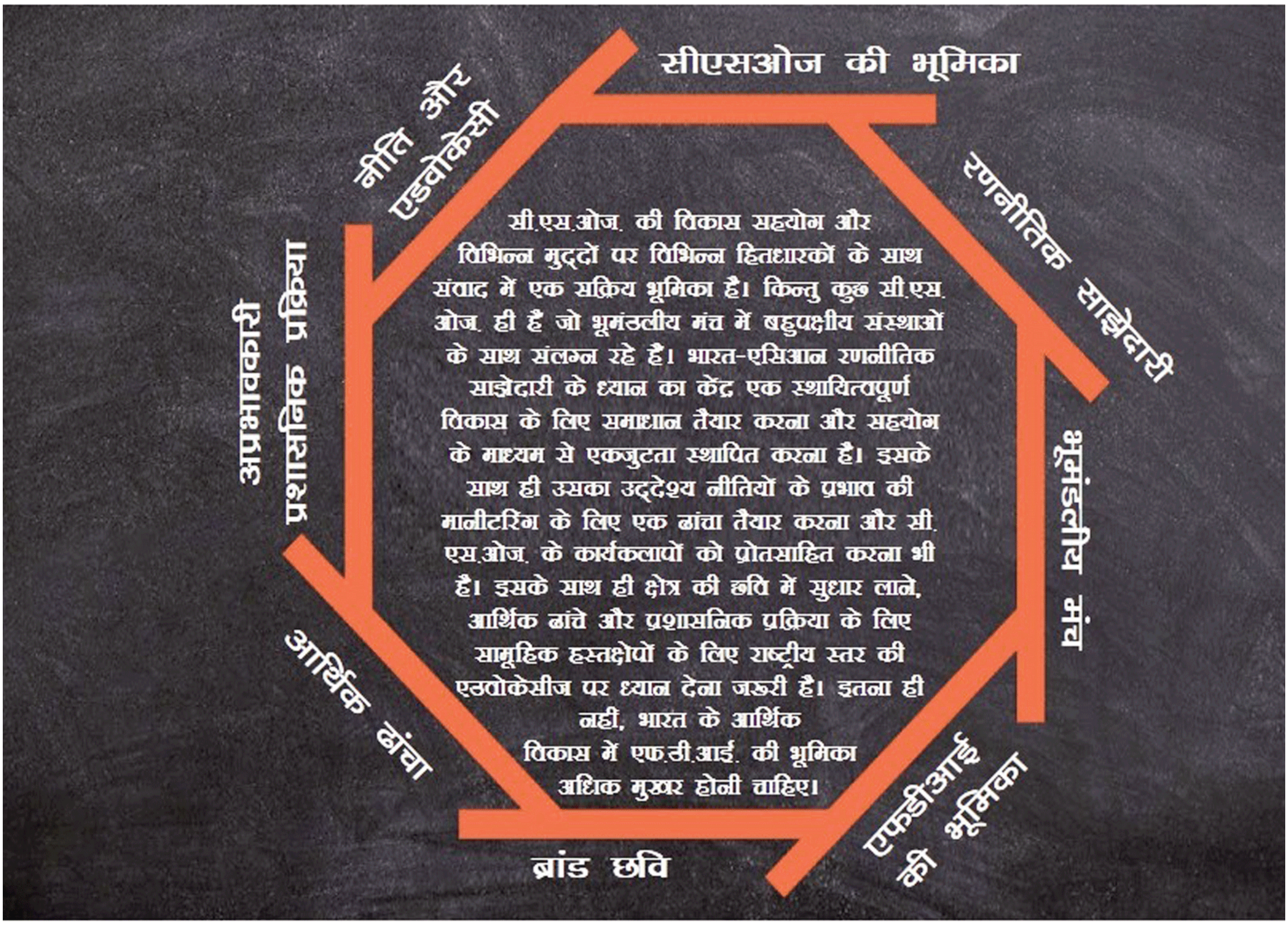

रूपांतरणकारी कार्रवाई और समावेशपूर्ण विकास हासिल करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसके अलावा, राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं ने भी नीतिगत संवाद, महत्वपूर्ण आकलन और मूल्यांकन में नागरिक समाज के संगठनों की भागीदारी के एक समर्थकारी या अनुकूल वातावरण प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई है।

स्थायित्वपूर्ण विकास पर एसिआन ने जो ध्यान केंद्रित किया है, उसने भारत के नागरिक समाज को नीतियों के आकलन और बहुपक्षीय मंचों में परिकल्पित परियोजनाओं और निवेशों में योगदान करने हेतु भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। भारतीय नागरिक समाज संगठनों की पहुंच जमीनी स्तर तक है। पिछले अनेक वर्षो में भारत के नागरिक समाज संगठन भारत के विकास सहयोग में संलग्न रहे हैं और अनुभव, इनपुट तथा डाटा प्रदान करने वाले कार्यतंत्रों में भाग लेते रहे हैं। भारत–एसिआन साझेदारी के लिए विकास उन्मुख

रही है और उसके आलोचनात्मक विश्लेषण की जरूरत है। इन पहलकदमियों के तौर–तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इनका वस्तुगत विश्लेषण करने की जरूरत है।

इस प्रकार, एक स्थायित्वपूर्ण और शांतिपूर्ण कार्यचालन के लिए एक नये विश्व की रचना की जरूरत है। इस प्रकार एसिआन को विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों के साथ रचनात्मक संलग्नता को बढ़ावा देना चाहिए और नागरिक समाज संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए यह ज्ञान और जानकारी के आदान–प्रदान के लिए एक नया मंच बन सकता है। एसिआन को नागरिक समाज के साथ कार्य के माध्यमों से क्षेत्रीय एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि एसिआन के साथ साझेदारी न केवल नये नेटवर्क निर्मित करने और पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्मित करने का अवसर है, बल्कि यह और अधिक आर्थिक एकीकरण का अवसर भी प्रदान करती है। यह साझेदारी उभरती शक्ति प्रतिस्पर्धाओं को भी संतुलित करेगी और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और संपन्नता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

भारत और एसिआन जब रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण में प्रविष्ट हो रहे हैं तब विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालने की संभावना मौजूद है। पहला है – वर्तमान और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों को व्यवस्थित करना क्योंकि भारत और एसिआन के लिए गैर–टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। भारत और एसिआन देशों की भौतिक क्षेत्रीय संपर्क के निर्माण में विशेष दिलचस्पी रही है। किन्तु सरकार द्वारा नये सिरे से प्रोत्साहन दिये जाने के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति न हो पाने के कारण बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में भारत की क्षमता को लेकर एक नकारात्मक सोच पैदा की है।

दूसरे, भारत और एसिआन को संवृद्धि और रोजगार के एक स्रोत के रूप में नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इक्नॉमी) से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। भारत और एसिआन को समुद्र केंद्रित आर्थिक विकास के लिए सहयोगकारी प्रयासों के साथ हिन्द महासागर में सुरक्षा पहलकदमियों को पूरित करना चाहिए। भारत ने खुले और मुक्त हिन्द–प्रशांत

के विचार को अनेक बार सामने रखा है। एसिआन–भारत और पूर्व भारत सम्मेलनों में भागीदारी एसिआन सदस्यों तथा व्यापकतर भारत–प्रशांत क्षेत्र के साथ कार्य को मजबूत बनाने में भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार यह एसिआन और पूर्व एशिया सम्मेलन राष्ट्रों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को एक नया वेग प्रदान करेगा।

तीसरे, तीव्र प्रौद्योगिकीय बदलाव और डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में भारत और एसिआन को समावेशपूर्ण संवृद्धि तथा साइबर सुरक्षा का विस्तार करने के लिए वर्तमान संस्थागत कार्यतंत्रों के स्तर को ऊपर उठाना होगा, नहीं तो इससे आय, डिजिटल पहुंच और अवसरों में असमानताएं बढ़ सकती हैं। भारत और एसियान को समावेशपूर्ण संवृद्धि को बल प्रदान करने हेतु ज्ञान साझाकरण और कार्य की सर्वोत्तम रीतियों को सुगम बनाना चाहिए। इसमें ब्राडबैंड संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए निजी क्षेत्र और सरकार के बीच आई.सी.टी. परामर्श शामिल किये जाने चाहिए।

चौथे, श्रमिकों सचलता को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पद्धतियों का विस्तार किया जाना चाहिए। एसिआन और भारत को बढ़े हुए देशांतरगमन या प्रवासन से महत्वपूर्ण रूप से लाभ हासिल होगा। नीतियों का उद्देश्य कौशल संबंधी अंतरों को भरना कौशल संबंधी असंतुलन को दूर करना, रोजगार संबंधी अंतरों को दूर करना और विदेश गये श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। द्विपक्षीय संपर्कों का विस्तार करने के लिए व्यवसाय और संपर्क का प्रभाव महत्वपूर्ण है। सामानों और सेवाओं, कुशल श्रमिकों और निवेशों की आवाजाही से इन संबंधों के और अधिक मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है।

अंत में, असवंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और डिजिटल विभाजन आदि की चुनौतियों के अलावा, अनेक दूसरे मुद्दे हैं जिन्हें एसिआन और भारत को हल करना हैः जैसे कि नागरिक समाज संगठनों और सरकारों के बीच अलगाव; क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चित भूराजनीतिक और सुरक्षा संबंधी स्थिति; संस्थागत ढांचे का विकास; क्षेत्र की समकालीन चुनौतियों के अनुरूप कार्य, आदि। किन्तु इन चुनौतियों से भारत और एसिआन को सहयोग के जबर्दस्त अवसर प्राप्त होंगे। वे इन जबर्दस्त चुनौतियों को निम्नलिखित के माध्यम से हल कर सकते हैंः नागरिक समाज संगठन, सहयोगपूर्ण शोध, क्षमता–निर्माण और निर्धनता उन्मूलन, जेंडर समानता, मौसम परिवर्तन आदि के क्षेत्र में क्षमता–निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक मुद्दे, समावेशपूर्ण संवृद्धि, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, नवाचार (इनोवेशन) तथा कौशलों का विस्तार।

एसिआन के लिए नागरिक समाज को शामिल करना आवश्यक होगा क्योंकि इससे एसिआन और नागरिक समाज दोनों को लाभ प्राप्त होगा। इससे नीति ढांचे, नागरिक स्थान आदि के संबंध में नागरिक समाज के मुद्दों को हल किया जा सकता है। एसिआन को नागरिक समाज संगठनों पर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना चाहिए, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसा करना चाहिए। इससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होंगे और क्षेत्रीय नागरिक समाज के साथ कार्य के माध्यम से और भी भीतर तक अपनी पहुंच बनायेंगे। इसके अलावा, भारत ने एफ.आई.डी.सी. के माध्यम से विकास सहयोग के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करनी शुरू की है जिससे नागरिक समाज और सरकार के बीच के अंतर को कुछ दूर करने में सफलता मिली।

डिजिटल संपर्क सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह भविष्य में जनता से जनता के बीच संपर्क को निरूपित कर सकता है। भारत की आधार–प्रणाली भारत–एसिआन फिनटेक कार्यक्रम को समरूप बनाती है या ई भुगतान प्रणालियों को जोड़ती है। एसिआन भारत–एसिआन वायु परिवहन समझौते सहित भौतिक संपर्क को बल प्रदान करने पर विचार कर रहा है। इससे इन क्षेत्रों में जनता से जनता के बीच प्रवाह का विस्तार होगा और भारत तथा एसिआन को नये और उभरते बाजारों – विशेषकर व्यवसाय, निवेश और पर्यटन के बाजारों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही हमारे लोगों को भारत के बेहतर भौतिक संपर्क में सुधार के प्रयासों के माध्यम से भूमि, वायु और समुद्री संपर्क का काफी अधिक लाभ से प्राप्त होगा।

इतना ही नहीं, यह पाया गया है कि इस तरह के प्रयास एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया को उन्मुक्त करते हैं जो भारत और एसिआन के बीच बेहतर संपर्क की दृष्टि से सकारात्मक विकास दबाव पैदा करती है। भारत और एसिआन के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं – संपर्क नेटवर्क में सुधार; सी.एल.एम.वी. क्षेत्र एस.एम.ई. सेक्टर में सहयोग, आई.टी.ई.सी. में सहयोग और क्षेत्र में निवेश प्रोन्ति एजेंसियों के साथ और अधिक मजबूत संबंध।

सहयोग का अगला चरण है क्षेत्र के लिए नये रास्ते तैयार करना और साथ ही भारत–एसिआन की प्रभावशाली साझेदारी को दृढ़ता से प्रस्तुत करना। तेजी से बदलती दुनिया और एसिआन के एकीकरण के संदर्भ में हमें अपनी–अपनी विदेश नीतियों पर निकटता से नजर डालनी होगी और एसिआन के भीतर यह परिचर्चा करनी होगी कि भविष्य में एसिआन किस दिशा में जा रहा है।

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंशिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेशनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिप: ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाता: रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिका: एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

वाणी वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) का संक्षिप्त परिचय

वाणी स्वैच्छिक विकास संस्थाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। इस समय वाणी के 540 सदस्य हैं जिनकी भारत की पहुंच 10000 स्वैच्छिक विकास संस्थाओं तक है। वाणी के सदस्यों में जीमनी स्तर की संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक शामिल हैं। वाणी के सदस्य देश के कुछ सबसे दूर–दराज के क्षेत्रों में अनेक प्राथमिकतापूर्ण विकास मुद्दों पर काम करते हैं जैसे कि शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मौसम परिवर्तन, जल और स्वच्छता, आपातकालीन प्रत्युत्तर और तैयारी, कृषि, निर्धनता, आदि। वर्ष 2017–18 में हमारे नेटवर्क ने बच्चों, विगलांगों, महिलाओं, वृद्धों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, विपदा पीड़ितों, बेरोजगारों, युवाओं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों, यौन कर्मियों सहित समाज असुरक्षित और सीमांमीकृत समूहों के 32 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई। अपने प्रयासों और रणनीतियों के माध्यम से वाणी का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी एक मजबूत नागरिक समाज का निर्माण करना है।

वाणी की स्थापना स्वैच्छिक कार्य को प्रोन्नत करने और मूल्य–आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई को पोषित करके स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए स्थान निर्मित करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। वाणी के हस्तक्षेप बाहरी और आंतरिक समर्थकारी वातावरण को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहे हैं। वाणी साक्ष्य–आधारित एडवोकेसी करती है जिसमें नियमनकारी ढांचे और संसाधन जनन शामिल हैं। यह उद्देश्य हासिल करने के लिए वाणी सरकार, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। वाणी परस्पर संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रमों और सूचना प्रचार–प्रसार के माध्यम से लचीलापन निर्मित करने और जवाबदेही, पारदर्शिता और अनुपालन को प्रोन्नत करने की दिशा में कार्य करती है। वाणी साक्ष्य–आधारित शोध आयोजित करके, अध्ययनों, लेखों और रिपोर्टों का प्रकाशन करके न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी एक संसाधन केंद्र बनने के लिए प्रयासरत है।

VANI
Celebrating 30 years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट,
सैक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077
फोन : 011–40391661, 40391663, टेलिफैक्स: 011–49148610
ईमेल: info@vaniindia.org, वेबसाइट: www.vaniindia.org